TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 229
दि. 20.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

ऊर्जा स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और भू-राजनीतिक अनुकूलता के अनुरूप: डॉ. जितेंद्र सिंह

'डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत कंप्यूटिंग जैसे कुछ क्षेत्रों को निर्बाध, स्थिर, चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली की आवश्यकता होती है, जहां परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है'

भारत पीछे नहीं चलेगा; यह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में विश्व का नेतृत्व करेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

स्वच्छ ऊर्जा अब केवल एक नीतिगत बहस नहीं, बल्कि जीवन शैली है: डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथि: 19 अ{उ 2025 5:04ढट्ु८ ढक्ष् ऊ'

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा स्वतंत्रता अब विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक आर्थिक, रणनीतिक और भूराजनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ और विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत का संक्रमण आत्मनिर्भरता और भूराजनीतिक अनुकूलता, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने पर होने वाली बहसें अब निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर यह सर्वमान्य है कि सतत विकास, आर्थिक मजबूती और भू-राजनीतिक अनुकूलता के लिए ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा, "यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने से न केवल आत्मनिर्भरता मजबूत होती है, बल्कि भारत अपरिहार्य वैश्विक बदलाव के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा निर्यातक देश स्वयं तेजी से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पुराने ऊर्जा मॉडलों पर टिके रहना पुरानी तकनीक से भावनात्मक रूप से चिपके रहने जैसा है, कल तो उसके पुर्जे भी नहीं मिलेंगे।'

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि देश अब निष्क्रिय भागीदार नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत अब वैश्विक रुझानों का अनुसरण नहीं कर रहा है; आज अन्य राष्ट्र मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं।' उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारतीय नवाचार वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचा रहा है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा की थी और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के सरकार के संकल्प को दोहराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को भेदभाव के नजरिए से नहीं, बल्कि उपयुक्तता, विश्वसनीयता और विशिष्ट अनुप्रयोग में उनकी उपयोगिता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, फिर भी कुछ क्षेत्रों—जैसे डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत कंप्यूटिंग—को निर्बाध, स्थिर, चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली की आवश्यकता होती है, जहाँ परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, 'भविष्य एक हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल में निहित है, जहाँ प्रत्येक स्रोत को वहाँ तैनात किया जाता है जहाँ वह सबसे अधिक लागत प्रभावी और कुशल हो।'

तकनीकी विकास से समानताएं बताते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब एक संतुलित 'एआई प्लस मानव बुद्धिमत्ता' मॉडल में विकसित हो रही है, उसी प्रकार भारत की ऊर्जा रणनीति भी नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन और अन्य उभरते समाधानों को मिलाकर एक एकीकृत ढांचे में परिपक्व होगी।

उन्होंने सरकार के साहसिक और अपरंपरागत सुधारों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोलना शामिल है। उन्होंने कहा, 'इस सरकार ने यथास्थिति से आगे बढ़ने का साहस दिखाया है, जिससे सार्वजनिक-निजी समन्वय संभव हो पाया है जो व्यापकता, गति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।'

मंत्री ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का आ'ान करते हुए कहा कि भारत को नवाचार और क्रियान्वयन के एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अलगाव और आपसी संदेह से ऊपर उठना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "राष्ट्रीय प्रगति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी, साझा उद्देश्य और एकीकृत कार्रवाई आवश्यक है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि ऊर्जा परिवर्तन के प्रारंभिक चरण में चुनौतियाँ अवश्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही राह पर मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने कहा, 'स्वच्छ ऊर्जा अब केवल सेमिनारों का विषय नहीं रह गया है; यह जीवनशैली का हिस्सा बन रही है। हितधारक होने के नाते, हम अनुकूलन करेंगे, नवाचार करेंगे और नेतृत्व करेंगे।'

संक्षिप्त समाचार

'जिसका खेत, उसकी रेत', हरियाणा में भी उठी पंजाब सरकार की पॉलिसी लागू करने की मांग

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को इस बार चर्चा किसी नए वादे या कागजी बहस की नहीं, बल्कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की उस नीति की हुई, जिसने जमीन पर किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया है। 'जिसका खेत, उसकी रेत' यह नीति अब पंजाब से निकलकर हरियाणा की राजनीति में भी गूंजने लगी है।

इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 'हरियाणा विधानसभा में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की शानदार नीतियों की गूंज सुनाई दी।

हंगामे से शुरू हुआ सत्र चाय पर चर्चा से खत्म, पास हुए ये अहम बिल

(जीएनएस)।

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे और गतिरोध के बाद आखिरी दिन चाय पर चर्चा के साथ निपट गया। लोकसभा स्पीकर की ओर से दी गई चाय पार्टी में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस पूरे सत्र में चुनाव सुधार, एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष का विरोध और हंगामा होता रहा। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर दोनों सदनों में चर्चा हुई।

इस सत्र में हुई तीखी बहसों और टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी के साथ हुआ। पिछले सत्र में विपक्ष ने इस चाय पार्टी का विरोध किया था। हालांकि, इस बार कई विपक्षी दल के नेता इसमें शरीक हुए।

– संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में कुल 8 विधेयक पास हुए। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चला और इसमें लोकसभा की 111% तथा राज्यसभा की 121% उत्पादकता दर्ज की गई।

– 1 दिसंबर से शुरू हुए सत्र में हंगामे से लेकर बिल फाड़ने और टीएमसी सांसदों के धरना जैसे नाटकीय घटनाक्रम भी हुए।

– VB-G RAM G विधेयक, 2025, शांति (SHANTI) विधेयक, 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (ऊी२२) विधेयक, 2025, विनियोग विधेयक (संख्या 4), 2025, निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 इस सत्र में पारित हुए।

– वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उलक्ष्य में सदन में 10 घंटे की चर्चा कराी गई। इस सत्र में चुनाव सुधारों पर भी संसद के दोनों सदनों में तीखी चर्चा हुई।

बिल फाड़ने से लेकर धरने तक की चर्चा

शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के साथ ही इस बार कई नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिले। विपक्ष ने मनरेगा बिल का नाम बदलने का तीखा विरोध किया। लोकसभा में बिल फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह के ऊपर कागज फेंक दिए। टीएमसी ने इस बिल के विरोध में आधी रात तक धरना भी दिया। हालांकि, इन सबके बावजूद इसे पास कराया गया। शांति बिल पर भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सत्र के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लगभग 3200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, प्रधानमंत्री नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बाराजागुली-कृष्णनगर खंड पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बारासात-बाराजागुली खंड पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4-लेन की आधारशिला रखेंगे, ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे। सुबह लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बाराजागुली-कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे।

सीएम योगी बोले- अखिलेश की माफिया के साथ तस्वीरें, जांच होने दीजिए...दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

लखनऊ (जीएनएस)। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन माफिया के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन-देन में संलिप्तता भी सामने आएगी। जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सपा प्रमुख की स्थिति वही है, 'यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।

सपा पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही

शुक्रवार को सत्र के पहले दिन योगी ने सदन में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के हर माफिया के संबंध सपा से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध सपा से रहे हैं।

सपा अपनी कार्यप्रणाली के लिए पहले से ही बदनाम और कुख्यात रही है। इस पूरे मामले में भी अपनी संलिप्तता उजागर होते हुए देखेगी। इस विषय में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोडीन फॉस्फेट एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एक औषधि है।

इसका उपयोग कोडीन-युक्त कफ सिरप के निर्माण में होता है। इसका कोटा और आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा केवल अधिकृत औषधि निर्माण के लिए ही किया जाता है। यह सिरप कई स्थानों पर नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था।

अवैध तस्करी की शिकायतें मिलने के बाद सरकार द्वारा कार्रवाई की गई।

एफएसडीए, जिला पुलिस और एसटीएफ द्वारा की जा रही कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी के मामलों का खुलासा हुआ और कई गिरफ्तारियां की गईं। इस मामले की निगरानी राज्य-स्तरीय एसआईटी कर रही है। अवैध तस्करी से जुड़े पहलुओं, जैसे धन कहां-कहां गया, इन तथ्यों का भी खुलासा होगा।

विज्ञापन

वांछितों की सपा प्रमुख के साथ फोटो लेकर आए ब्रजेश पाठक

कोडीन कफ सिरप मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नया खुलासा किया। कफ सिरप मामले के वांछितों की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर मीडिया से साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के दाएं और बाएं खड़े कफ सिरप में वांछित लोगों से क्या रिश्ते हैं, वह इसे स्पष्ट करें।

सपा कफ सिरप के वांछितों को क्यों सम्मान देने का काम कर रही है। ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये समूह सपा के सदस्य हैं। इनका पालन पोषण सपा ने किया है। सपा अपना पाप सरकार पर मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट- वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी की ओर धकेलने वाले सपा के लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें।

राष्ट्रपति ने हैदराबाद में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

लोक सेवा आयोगों को न केवल अवसर की समानता के आदर्श से निर्देशित होना चाहिए, बल्कि परिणामों की समानता के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

लोक सेवा आयोगों को भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा और समग्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना के हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निमार्ताओं ने संविधान का एक पूरा भाग सेवाओं और लोक सेवा आयोगों को समर्पित किया है। यह केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की भूमिकाओं और कार्यों को दिए गए महत्व को दशार्ता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा समान अवसर और प्रतिष्ठा के हमारे संवैधानिक आदर्श लोक सेवा आयोगों के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

संविधान की प्रस्तावना, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का मौलिक अधिकार और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देशित करने वाले निर्देशक सिद्धांत, लोक सेवा आयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक सेवा आयोगों को न केवल समान अवसर के आदर्श से निर्देशित होना चाहिए, बल्कि परिणामों की समानता के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

डॉ. विशाल सिंह (फूड मैन) ने आयोजित की अपनत्व भरी पार्टी । आईना परिवार के साथ पहुंची कई महान विभूतियां

लखनऊ, फूड मैन के नाम से प्रख्यात भारत सहित विश्व के कई देशों में अलग पहचान बनाने वाले , गरीबों भूखों और तीमारदारों को भोजन देने वाले, करोना काल में निस्वार्थ लोगों की मदद करने वाले, सेवादार डॉ विशाल सिंह आज जाते हुए वर्ष के अवसर पर अपने यहां गीत गजल और आत्मिक भोजन का आयोजन किया जिसमें आईना परिवार के साथ पी एम डब्ल्यू जे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, एन आलम, जमील मलिक,सरफराज जाहिद, आईना परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मोहम्मद कामरान, प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुरमीत कौर, मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के संयुक्त सचिव अनिल सैनी , सदस्या रेनू निगम, सर्वजीत कौर, हेमंत चंदानी सहित दर्जनों पत्रकार सेवादार और कई महान विभूतियां सम्मिलित हुई ।

जैसा कि विशाल सिंह का आज से कुछ माह पूर्व उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लौटते समय डॉ विशाल

सिंह का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन नेक दिल इंसान और गरीबों की मदद से मिली दुआओं के कारण मौत पर अपनी विजय प्राप्त कर आज हम लोगों के बीच यह जिंदा दिल इंसान मौजूद हैं। आईना परिवार के प्रतिनिधि एवं सेवादार साथी डॉ. विशाल सिंह (फूड मैन) को आईना परिवार ने आयोजन में पहुंचकर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीघार्यु जीवन की कामना की।

भेंट के दौरान आईना परिवार द्वारा आयोजित होने जा रहे प्रतिष्ठित ह्लअटल सम्मानह्व कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. विशाल सिंह (फूडमैन) को सम्मानित किए जाने हेतु औपचारिक निमंत्रण भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर भाई नूर ने अपने गीतों से समा बांध दिया। बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ सभी ने आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया कार्यक्रम मे आए अतिथियों ने रंगारंग के साथ चार चांद लगा दिए। कभी ना विस्मृत होने वाले कार्यक्रम में कई व्यंजनों के साथ लाजवाब चोखा बाटी का सभी ने स्वाद लिया।

कार्यक्रम को लेकर आपसी संवाद, आत्मीयता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच आईना परिवार के सदस्यों ने शुभकामनाओं के साथ हल्के-फुल्के क्षण साझा किए, जिससे माहौल सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण रहा।

डॉ. विशाल सिंह (फूड मैन) ने आईना परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा, संवेदना और सामाजिक सहयोग ही समाज को सशक्त बनाते हैं।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) समुद्री क्षेत्र, ब्रिज एवं टनल इंजीनियरिंग, रक्षा लॉजिस्टिक्स और मल्टीमॉडल परिवहन योजना को आगे बढ़ाएगा - श्री अश्विनी वैष्णव

गति शक्ति विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी कोर्ट की दूसरी बैठक आयोजित

(जीएनएस)।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) ने नई दिल्ली के रेल भवन में अपनी दूसरी कोर्ट मीटिंग आयोजित की। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में श्री अश्विनी वैष्णव (रेलवे, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जीएसवी ने अपने परिचालन के तीन वर्षों के अंदर ही उद्योग-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ अभूतपूर्व प्रगति की है और देश के लिए एक आदर्श संस्थान बन गया है। रेलवे और विमानन क्षेत्रों पर अपना मजबूत ध्यान केंद्रित करते हुए, जीएसवी पुल और सुरंग इंजीनियरिंग, समुद्री क्षेत्र (जहाज निर्माण पर विशेष) के पाठ्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाएगा, रक्षा बलों और रेलवे के कौशल विकास में अधिक योगदान देगा और एकीकृत परिवहन योजना के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करेगा।

इस बैठक में शुभांगिनी राजे गायकवाड़ (बड़ौदा की राजमाता), श्री सतीश कुमार (अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड), लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह (सेना के उप प्रमुख), श्री अमरदीप सिंह भाटिया (सचिव, डीपीआईआईटी), श्री टीपी सिंह (डीजी-बीआईएसएजी), प्रोफेसर रजत मूना (निदेशक, आईआईटी जीएन), नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एमओआरटीएच, एल एंड टी, एएमडी जैसे प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि और गति शक्ति विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रोफेसर मनोज चौधरी (कुलपति, जीएसवी) ने प्रगति और स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी सदस्यों ने इतने कम समय में विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट प्रगति, विशेष रूप से उद्योग जगत के साथ सहयोग, रेलवे और रक्षा बलों के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण तथा सिविल सेवाओं के लिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा की। कोर्ट के सदस्यों ने पुल और सुरंग इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण, रेलवे, रक्षा क्षेत्र, रसद और आपूर्ति श्रृंखला में भविष्य की प्रगति के लिए कई सुझाव और सहयोगात्मक इनपुट दिए। सेना उप-प्रमुख ने भारतीय सेना की संबंधित अकादमियों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दायरे और विस्तार को बढ़ाने की वकालत की। विश्वविद्यालय इस वर्ष से भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) अधिकारियों के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं संचालित करेगा तथा अधिक चेयर प्रोफेसरशिप की स्थापना के लिए उद्योगों के साथ मिलकर काम करेगा।

इस अवसर पर, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजी) और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने पीएम गति शक्ति को और गति देने के लिए समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जबकि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) ने गति शक्ति विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सुविधा के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। अतिरिक्त कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है और अतिरिक्त कैंपस के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

गति शक्ति विश्वविद्यालय, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय है, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा 2022 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत यह विश्वविद्यालय रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, समुद्री परिवहन, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच उद्यमिता बढ़ाने और उनके द्वारा संचालित उद्यमों से अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना कार्यान्वित कर रहा है

एकल स्थल पंजीकरण योजना से एमएसई को वित्तीय सहायता मिल रही है

विपणन सहायक योजना अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता प्रदान करती है; इस योजना से 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी लाभान्वित हुए हैं

(जीएनएस)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय-एमएसएमई अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में उद्यमिता बढ़ाने और अनुसूचित जाति/जनजाति संचालित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना-एनएसएसएचए कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की कई पहल की गई हैं, जिनमें क्षमतावर्धन कार्यक्रम; बाजार से संबद्ध करने, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कार्यशाला/जागरूकता अभियान, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर सहायता, एकल स्थल पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल पर नामांकन आदि शामिल हैं।

एनएसएसएचए योजना के विशेष विपणन सहायक घटक-एसएमएएस के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की क्षमता सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुगमता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को 36.41 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

एनएसएसएचए योजना के तहत विभिन्न लाभों की जानकारी देने के लिए; देश में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार और विशेष रूप से लक्षित दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सक्रियता से इस्तेमाल किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्र ने तमिलनाडु में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत 127 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 127.586 करोड़ रु की राशि जारी की है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त है। यह अनुदान विधिवत निर्वाचित और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 9 जिला पंचायतों, 74 ब्लॉक पंचायतों और 2,901 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किया गया हैं।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की अनुशंसा करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किए जाते हैं। अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, किया जाएगा। प्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिनमें: (क) स्वच्छता और 'खुले में शौच मुक्त' स्थिति को बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए; और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CREDAI के राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @ 2047' को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उपएउअक के राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @ 2047' को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे सामने 2047 तक हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम भारत के निर्माण और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाली एक बेंचमार्क पर पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में Next Gen इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए और कई प्रकार की नई पहल ने हमारे अर्बन डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ स्ट्रक्चर्ड किया बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले देशों के करीब पहुंचने के लिए एक रोडमैप भी बनाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट में कई पहल की गईं हैं और हर क्षेत्र की बाधाएं दूर करने का भी प्रयास किया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि CREDAI ने 20 लाख पौधे लगाकर 25 गांवों की 9 हजार एकड़ बंजर भूमि को फिर से हराभरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर डेवलपर को प्रोजेक्ट डिजाइन करते हुए थोड़ा ग्रीन एरिया को ध्यान में रखकर डिजाइन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर डेवलपर अपने हर क्रिएशन में बिल्डिंग बनते समय 10 अच्छे वृक्ष लगाने का प्रयास करता है तो यह बहुत अच्छा काम होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1999 से लेकर आज तक CREDAI ने हाउसिंग और हेबिटेट को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को सतत रूप से हासिल किया है। उन्होंने कहा कि CREDAI ने हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिक प्रथाओं को सर्वोपरि रखा और CREDAI के करण ही आज डेवलपर्स के काम को क्रेडिट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी बैलेंसशीट अच्छी होनी जरूरी नहीं है बल्कि हमारे काम के बारे में समाज में अच्छी साख होना भी बहुत जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि CREDAI ने भारत की निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक शीर्ष संस्था के रूप में इस क्षेत्र को स्ट्रक्चर्ड और स्वीकृत क्षेत्र बनाने का बहुत बड़ा काम किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि उपएउअक आज 21 राज्यों के 230 शहरों में मौजूद है और लगभग 13 हजार डेवलपर्स का एक विशाल वट वृक्ष आज खड़ा है। उन्होंने कहा कि CREDAI ने अपने 25 साल पूरे कर इस क्षेत्र में अपनी जरूरत को भी साबित किया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में CREDAI ने अपने मानवीय चेहरे को भी उजागर किया है और लगभग 3 लाख से अधिक मजदूरों का भी प्रशिक्षण किया है। श्री शाह ने कहा कि हमें इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि मजदूर को किस क्षेत्र में स्किलिंग की जरूरत है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण बढ़कर 2035 तक 40 प्रतिशत तक हो जाएगा और 2047 तक देश की 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 50 प्रतिशत जिस शहरी क्षेत्र में रहती हो, तो उसके हाउसिंग की व्यवस्था का ज़िम्मा डेवलपर्स पर ही है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री शाह ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के अनुसार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन हाउसिंग का सैचुरेशन रेश्यो लाने के लिए अफोर्डेबल, इको-फ्रेंडली और बेहतर जीवन स्तर वाले हाउसिंग की दिशा में उपएउअक को एक टीम बनाकर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समय आधारित अप्रूवल, ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटलाइज्ड रेकॉर्ड्स ने इस क्षेत्र में आर्किटेक्चर का एक विश्वास अर्जित किया है जिसे हम और तेज गति से आगे ले जाने वाले हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि फएफअ इस क्षेत्र के सुधार में एक structural breakthrough था जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कहा कि home buyers के हितों की रक्षा, निष्पक्ष लेनदेन और गुवत्तायुक्त निर्माण को सुनिश्चित करने की दिशा में RERA ने हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया है और 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि 29 राज्यों में अपील का प्राधिकरण भी गठित हो चुका है और 29 RERA प्राधिकरणों ने अपनी वेबसाइट्स भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख 55 हजार रियल एस्टेट परियोजनाएं फएफअ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1 लाख 10 हजार डेवलपर्स भी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने GST का सबसे अधिक फायदा अगर किसी सेक्टर को पहुंचाया है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। उन्होने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी को 8 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया, आवास योजनाओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, सीमेंट पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, संगमरमर, ग्रेनाइट, रेत, चूना और ईंट पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, बांस फ्लोरिंग पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर एक बिल्डिंग बनने पर खर्च में नए सुधारों से 5 से 7 प्रतिशत की कमी की संभावना बन गई है। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत FDI को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी है और नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड भी जारी किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार इस सेक्टर के महत्व को समझती है और इसके माध्यम से हर व्यक्ति को अपना एक घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा हम CREDAI के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने बड़े डेवपूलपर्स से कहा कि क्या वे बड़ी योजना बनातेहुए साथ में ही एक कम लागत वाली हाउसिंग बनाना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे हम अपने सेक्टर की जरूरत के रूप में लेते हैं तो आने वाले दिनों में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 सहित इस क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी CREDAI को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, ऊर्जा सक्षम डिजाइन, वाटर रिसाइक्लिंग, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को हमें हउसिंग का न्यू नॉर्मल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजाइन का हिस्सा सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि रहने वाले के अच्छे जीवन के लिए इन सभा को अपने डिजाइन का हिस्सा बनाना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें लैंड मार्केट को अधिक पारदर्शी बनाना होगा और शहरों को अब लैंड बैंकिंग और सट्टात्मक होल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर का जाल बिछाने और सडकें बनाने से लेकर इको फ्रेंडली बिजली उत्पादन तक कई काम किए हैं जो शहर को रहने योग्य बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं।

नियात कार्गो एक्सप्रेस इच्छापुरी, गुरुग्राम से मुंद्रा पोर्ट तक चलाई जा रही है

सुनिश्चित रेल सेवा से निर्यात में तेजी और लागत प्रभाविता संभव हुई है

(जीएनएस)।

रेलवे, माल ढुलाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए निर्यात केंद्रित, सुनिश्चित ढुलाई सेवा, निर्यात कार्गो एक्सप्रेस गुरुग्राम के इच्छापुरी कंटेनर टर्मिनल से मुंद्रा बंदरगाह तक डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन के रूप में संचालित कर रही है। इससे पहले गुरुग्राम के गढ़ी से सुनिश्चित माल ढुलाई सेवा की 20 खेप संचालित हुई है। समय सारणीबद्ध रेल ढुलाई सेवा गुरुग्राम के इच्छापुरी से पहली बार

संचालित की जा रही है।

मुंद्रा बंदरगाह तक सुनिश्चित और समयबद्ध यह साप्ताहिक सेवा, माल की तेज, विश्वसनीय और अनुमानित समय में ढुलाई करेगी और निर्यातकों के लिए सहायक होगी, जिससे माल पहुंचने में विलंब और प्रचालन लागत में कमी आएगी।

उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल निर्यातकों के लिए सुनिश्चित माल ढुलाई सेवा संचालित कर रहा है। विशेष रूप से संचालित इस मालगाड़ी से न्यूनतम ठहराव, निर्बाध आवागमन, माल की तेज ढुलाई समय पर हो रही है। यह उच्च मूल्य निर्यात कार्गो के लिए विशेष रूप से बहुत उपयोगी है।

कपास पर आयात शुल्क और कम कीमत

(जीएनएस)।

सरकार को जानकारी है कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क की छूट देने ने घरेलू कीमतों में कमी आयी है। शुल्क में छूट मिलने बाद से, समतुल्य एस-6 कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो दिनांक 19.08.2025 मेंलगभग 79.15 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड थी वह दिसंबर 2025 में गिरकर लगभग 73.95 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड हो गईं, जो वैश्विक स्तर पर गिरावट को दशार्ता है। घरेलू स्तर पर भी कपास की कीमतों में इसी प्रकारर की कमी देखी गई है, जो लगभग 57,000 रुपये प्रति कैंडी से घटकर लगभग 52,500 रुपये प्रति कैंडी हो गई है। यह कमी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलावों के अनुरूप है। घरेलू कीमतें वैश्विक एवं घरेलू मांग-आपूर्ति की स्थितियों, विनिमय दर और गुणवत्ता संबंधी कारकों से प्रभावित होती हैं। 2024-25 मौसम के दौरान कपास का आयात कुल घरेलू खपत का लगभग 13.93 प्रतिशत था। छूट के बाद से कीमतें कम हो गई हैं, जो वर्तमान में प्रति कैंडी 51,500 रुपये से 52,500 रुपये के बीच हैं, जिससे उद्योग के लिए किफायती है जबकि एमएसपी-आधारित समर्थन किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से कपास किसानों को सहायता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाग मिलता है। 2025-26 मौसम के लिए, मध्यम रेशे वाली कपास के लिए एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो 2024-25 की तुलना में 589 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। किसानों को मजबूरी में कपास बेचने से रोकने के लिए, भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने 11.12.2025 तक एमएसपी के अंतर्गत 11 राज्यों के 149 जिलों में 570 खरीद केंद्रों के माध्यम से लगभग 31.19 लाख गांठें खरीदी हैं, जिनकी कीमत 13,492 करोड़ रुपये है।

भारत के घरेलू वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता एवं आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका से कपास का आयात बढ़ा है, जो भारत की लगभग 94 प्रतिशत कपास की खपत करता है। अगस्त-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, जिसमें 11 प्रतिशत आयात शुल्क की अस्थायी छूट प्रदान करने के बाद की अवधि भी शामिल है, अमेरिका से कपास का आयात उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है। कुल मिलाकर, भारत में कपास का आयात 2023-24 में 15.20 लाख गांठों से बढ़कर 2024-25 में 41.40 लाख गांठें रहा, जिससे मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिली। ये आयात विशेष प्रकार की कपास उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत के वस्त्र क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। एमएसपी द्वारा किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने एवं उचित लाभ सुनिश्चित किया जाता है।

डीडीडब्ल्यूएस ने 8 राज्यों के 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में स्थानीय भाषा में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया

केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने गुजरात के मेहसाना जिले के जाहिरपुरा गांव में गुजराती में लोगों से बातचीत की

राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने कर्नाटक के उडुपी जिले के कोडी गांव में कन्नड़ में लोगों से बातचीत की

स्थानीय भाषा में ग्रामीण समुदायों के साथ संवाद से 'जन भागीदारी' और समुदाय-नेतृत्व वाली जल व्यवस्था को मजबूती मिलती है

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने आज 'सुजल ग्राम संवाद' के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया । यह सहभागी जल शासन और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के समुदाय-नेतृत्व वाले कार्यान्वयन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता

है ।

इस वर्चुअल संवाद में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, सामुदायिक प्रतिभागियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं के साथ-साथ जिला कलेक्टर/उपायुक्त, जिला पंचायतों के सीईओ, डीडब्ल्यूएसएम अधिकारी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए ।

सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण में 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया , जो समुदायों और अधिकारियों दोनों की मजबूत भागीदारी को दशार्ता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों ने बड़े समूहों में संवाद में भाग लिया , जिनमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग समुदाय के सदस्य शामिल थे, जिनकी सामूहिक भागीदारी पंजीकृत संख्या से कहीं अधिक थी।

एक मेज पर बैठे पुरुषों का एक समूह - एआई द्वारा उत्पन्न सामग्री गलत हो सकती है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले 8 गांवों के साथ ग्राम स्तरीय वार्ता आयोजित की गई । केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के मेहसाना जिले के जहीरपुरा गांव के ग्रामीणों से गुजराती में बातचीत की , जबकि राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने कर्नाटक के उडुपी जिले के कोडी गांव के ग्रामीणों से कन्नड़ में बातचीत की ।

निफ्ट ने विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2026-27 बैच की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क घटाया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2026-27 बैच के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 6 जनवरी 2026 है (7 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक विलम्ब शुल्क के साथ) और परीक्षा की तिथि 8 फरवरी 2026 है।

सीबीटी और पेन-पेपर आधारित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर के 100 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी।

वर्ष 2026-27 बैच के लिए, शुल्क 3,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, जो ओपन, ओबीसी (एनसीएल) के लिए है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

भाजपा और संघ को भी मंजूर हो ऐसे व्यक्तिव वाले नबीन बाबू बने कार्यकारी अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय जनता पाटा ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को पाटा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सबको चौंका दिया है। शायद ही किसी ने उम्मीद की हो कि नबीन बाबू को इतना महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। पिछले कई महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनने वाली है क्योंकि श्री नड्डा का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका था और वह एक्सटेंशन पर चल रहे थे। नितिन नबीन भाजपा के इतिहास में जेपी नड्डा के बाद दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। पाटा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई औपचारिक पद नहीं है। लेकिन साल 2019 के बाद से भाजपा में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की एक परंपरा शुरू हुई है। भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब होगा अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में पाटा के शीर्ष नेताओं के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी में ये प्राव्रिया पूरी की जा सकती है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी जनवरी तक ही है। ऐसे में से सवाल उठ रहा है कि जब वुछ दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है तो पाटा ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है? इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है लेकिन ये माना जा रहा है कि पाटा अपने संविधान के हिसाब से होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को आम सहमति और निर्विरोध रूप से करना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि भाजपा जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्राव्रिया शुरू करेगी। पाटा में इसकी एक औपचारिक प्राव्रिया है। ऐसे तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन नामांकन तिथि, चुनाव तिथि में औपचारिक प्राव्रियाएं हैं, पाटा को इन्हें करना है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि नितिन नबीन ही अगले अध्यक्ष होंगे। भाजपा में अध्यक्ष को चुनने की एक लंबी प्राव्रिया है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन सिन्हा को पाटा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने जाने वाले नितिन नबीन 5 बार से लगातार विधायक हैं और भाजपा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 45 साल के नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना जरूर कई लोगों को हैरान कर रहा है लेकिन विश्लेषक इससे हैरान नहीं हैं। बिहार चुनावों के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन से दो घंटे मुलाकात की थी। नितिन नबीन पाटा के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के प्राभारी थे और भाजपा ने यह चुनाव भारी बहुमत से जीता था। यानी नितिन नबीन अपनी संगठनात्मक क्षमता पहले ही साबित कर चुके हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन नबीन की नियुक्ति के पीछे कोई खास वजह या पाटा की कोई खास रणनीति है? विश्लेषक मानते हैं कि पाटा में ये बदलाव का दौर है और ये समय की जरूरत के हिसाब से उठाया गया कदम है। विजय त्रिवेदी और विनोद शर्मा दोनों ही मानते हैं कि पाटा जेनरेट्स चेंज यानि पीढ़ीगत बदलाव से गुजर रही है। पाटा में पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह नए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रादेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में पुराने नेताओं को हटाना और नए चेहरों को लाना पाटा की इसी रणनीति का हिस्सा है और नितिन नबीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना इस कड़ी में अगला कदम है। पाटा नए नेतृत्व को आगे लाना चाहती है और ये नियुक्ति भी उसी दिशा में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाजपा में ऐसे नेताओं को आगे लाया जा रहा है जो किसी भी तरह से नरेन्द्र मोदी या अमित शाह के लिए चुनौती पेश न करें। विनोद शर्मा कहते हैं, नितिन नबीन की नियुक्ति हैरान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें अमित शाह की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है। किसी भी ऐसे नेता को मजबूत पद पर नहीं लाया जा रहा है जो आगे चलकर किसी भी तरह की शीर्ष नेतृत्व को चुनौती पेश कर सके। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो भाजपा और संघ को भी मंजूर हो।

एमआईसीई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय शहरों में कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना करेगा

डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना ही भारत को भविष्य के लिए तैयार वैश्विक एमआईसीई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी है: श्री सुमन बिल्ला

(जीएनएस)।

भारत सरकार का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, देश के मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन और एग्जीबिशन (एमआईसीई) टूरिज्म इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2026 से हितधारकों के साथ साझेदारी में स्वतंत्र निकायों के रूप में शहरों में कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।

यह बात पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव और महानिदेशक श्री सुमन बिल्ला ने आज नई दिल्ली में इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) द्वारा आयोजित आईईआईए इवेंट-टेक और मारटेक समिट 2025 के उद्घाटन के दौरान कही।

सभा को संबोधित करते हुए श्री बिल्ला ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्य अपने अनूठे तरीकों से पर्यटन के अवसरों को खोल रहे हैं और अब भारत को वैश्विक एमआईसीई मैप पर प्रमुखता से स्थापित करने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे आइकॉनिक वेन्यू उपलब्ध होने और इन्क्रेडिबल इंडिया कैंपेन के तहत एमआईसीई पर्यटन को प्राथमिकता दिए जाने के साथ, हमारा उद्देश्य कई भारतीय शहरों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एमआईसीई डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है।

संस्थानिक सुधारों के महत्व पर जोर देते हुए, श्री बिल्ला ने कहा कि प्रोफेशनल सिटी एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना भारत की नेशनल एमआईसीई रणनीति का आधार स्तंभ बनेगी। ये ब्यूरो स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे, जो वैश्विक आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वित और विश्व स्तरीय सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना है।

प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए, श्री बिल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की योजना, मैनेजमेंट और डिलीवरी को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एमआईसीई क्षेत्र को उन्नत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल परिवर्तन समाधानों को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि अपने प्रमुख आयोजन स्थलों में स्मार्ट तकनीकों को एकीकृत करके, अनुमतियों और स्थानीय भागीदारों के नेटवर्किंग के लिए एक एकल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए, इस ढांचे का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक नेशनल बाजार में प्रेडिक्टिव इनसाइट्स जेनरेट करके और पूरे इकोसिस्टम में डिजिटल तौर-तरीकों को तेजी से अपनाकर, भारत एक भविष्य के लिए तैयार प्रदर्शनी और इवेंट गंतव्य के रूप में मजबूती से स्थापित होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) के अध्यक्ष, श्री सोराज धवन ने कहा कि आईईआईए भारत को दुनिया के शीर्ष पांच एग्जीबिशन मार्केट में शामिल करने के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का भारत का एमआईसीई बाजार, 2030 तक बढ़कर 103.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि इस वृद्धि को हासिल करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित प्रोफेशनल सिटी एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना की राष्ट्रीय रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ब्यूरो इवेंट आयोजकों के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेंगे, जिससे व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार होगा और इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इकोसिस्टम की समस्या का समाधान होगा।

श्री धवन ने आगे कहा कि सिटी एमआईसीई ब्यूरो स्थानीय भागीदारों और प्रोफेशनल सहायता का एक वेरिफाइड नेटवर्क प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय आयोजकों के लिए मार्केट में एंट्री के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रोफेशनलिज्म और प्रदर्शनी आयोजन के लिए बीआईएस मानकों को अपनाना, भारत में बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अगले पांच वर्षों के लिए भारतीय एमआईसीई उद्योग का रोडमैप विषय पर आयोजित एक गोलमेज शिखर सम्मेलन था। इसके साथ ही, आईईआईए की रणनीतिक रिपोर्ट "इंडिया एमआईसीई अपॉर्चुनिटीज ओवरव्यू (2025-2030)" का आधिकारिक विमोचन भी किया गया। यह रिपोर्ट वैश्विक एमआईसीई क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए संस्थानिक सहायता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

इंडियन एक्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईईआईए) एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है, जो प्रदर्शनी आयोजकों, आयोजन स्थल स्वामियों और सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आईईआईए "भारतीय व्यापार मेलों के प्रवेश द्वार" के रूप में कार्य करता है, जो प्रदर्शनी उद्योग को आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में आगे बढ़ा रहा है।

जैविक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाव

सरकार उर्वरकों की स्थिर कीमतें और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, साथ ही किसानों की सहायता के लिए जैविक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है

(जीएनएस)।

यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य साल 2018 से स्थिर बना हुआ है। इसी तरह, डीऐपी की कीमतें भी पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) से स्थिर हैं। इन कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए, भारत सरकार यूरिया और फॉस्फेटिक व पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों, दोनों पर सब्सिडी का बोझ खुद उठा रही है। यूरिया पर होने वाला वास्तविक खर्च प्राकृतिक गैस की कीमतों, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल की लागत और यूरिया के अंतरराष्ट्रीय आयात मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलता रहता है। वहीं, पीएंडके योजना के तहत, अधिसूचित उर्वरकों पर वार्षिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक निश्चित राशि तय की जाती है।

उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक बुवाई सीजन शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उर्वरकों की राज्यवार और महीने के अनुसार आवश्यकता का आकलन करता है। इस अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में की जाती है। उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। साथ ही, राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांग भेजकर आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए निमार्ताओं और आयातकों के साथ समन्वय बनाए रखें।

भारत सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑयल केक, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले और नैनो फर्टिलाइजर जैसे वैकल्पिक फर्टिलाइजर को नोटिफाई किया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से और पूर्वोत्तर राज्यों में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ₹15,000 प्रति हेक्टेयर की राशि किसानों को जैविक खाद सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। वहीं, एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों में ₹46,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से ₹32,500 प्रति हेक्टेयर की राशि ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए निर्धारित है, जिसमें ₹15,000 की राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है। यह योजना 2014-15 से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी सभी खेतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) प्रदान करना है, ताकि उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। किसानों के खेतों की मिट्टी का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि कम से कम 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा सके। 2014-15 से अब तक देश भर में 25.61 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार और वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत शुरूआत से अब तक 1970 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही, देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन और 7,425 किसान मेलों या अभियानों का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

पीएम गतिशक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए 105वीं एनपीजी बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आज नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 105वीं बैठक बुलाई गई। बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुसार मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनपीजी ने 07 रेल परियोजनाओं और 01 सड़क परियोजना का मूल्यांकन किया जिससे पीएम गतिशक्ति के एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों और आर्थिक तथा सामाजिक केंद्रों के अंतिम छोर तक संपर्क के सरकार के समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन हो सके। पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप उम्मीद है कि इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी, यात्रा में लगने वाला समय कम होगा, और परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेंगे। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अपेक्षित प्रभावों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रोजेक्ट्स का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

रेल मंत्रालय

i. तीसरी और चौथी लाइन अराक्कोनम - रेनिगुंटा

रेल मंत्रालय ने बढ़ते यात्रियों की मांग को पूरा करने, लाइन क्षमता बढ़ाने, रेलगाड़ियों को समय पर चलाने और बढ़ती माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए अराक्कोनम और रेनिगुंटा के बीच 76.559 किमी लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह कॉरिडोर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जिलों को जोड़ने वाला है और "मिशन 3000 एमटी" और अत्यधिक घनत्व वाले यातायात मार्गों (अमृत चतुर्भुज) कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है।

इस प्रस्ताव से पूर्व उद्योग जगत से विचार-विमर्श किया गया है ताकि इस रेलवे लाइन का निर्माण ऐसे क्षेत्रों से हो

जहां से प्रमुख राजमार्गों और हवाई अड्डों से संपर्क सुनिश्चित हो सके, और उद्योग केंद्रों तथा प्रमुख ट्रांसपोर्ट नोड्स जुड़ सकें और मजबूत मल्टीमॉडल लिंक का लाभ मिले। माल लादने के लिए बेहतर संपर्क सड़कें ढुलाई की दक्षता को और मजबूत करेंगी। मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि यह परियोजना रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक निवेश है।

ii. इरोड - करूर सेक्शन के बीच दोहरिकरण

रेल मंत्रालय ने भीड़ कम करने, क्षमता बढ़ाने और यात्री तथा माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए संचालन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु में 66.67 किमी लंबी इरोड-करूर रेलवे लाइन के दोहरिकरण का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना कम दूरी वाले माल ढुलाई मार्गों को मदद करेगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय गतिशीलता को मजबूत करेगी।

इस कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यों के राजमार्गों, हवाई संपर्क और औद्योगिक केंद्रों से मौजूदा सड़क लिंक के साथ मजबूत जुड़ाव सहज मल्टीमॉडल परिवहन को सक्षम करेगा। लाइन को डबल करने से कोयला, स्टील, सीमेंट और ग्रेनाइट जैसी प्रमुख वस्तुओं की बिजली संयंत्रों और उद्योगों तक आवाजाही में भी सुधार होगा, जिसे लोडिंग पॉइंट्स तक पर्याप्त संपर्क सड़क मार्गों से मदद मिलेगी।

मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि यह परियोजना आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करते हुए संपर्क में सुधार करेगी, और तमिलनाडु के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होगी।

iii. गुंटाकल - बेल्लारी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने गुंटकल और बेल्लारी के बीच 45.92 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मौजूदा डबल-लाइन कॉरिडोर की क्षमता चार गुना हो जाएगी। यह परियोजना जेएसडब्ल्यू, कल्याणी स्टील्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट और केपीसीएल जैसे प्रमुख उद्योगों को सेवा देने वाले एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई और यात्री मार्ग पर क्षमता को बढ़ाने वाली होगी।

हुबली-गडग-बेल्लारी-गुंटकल मार्ग पर स्थित यह महत्वपूर्ण रेल खंड, उत्तर-पश्चिम कर्नाटक को सम्पूर्ण भारत के प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है। बेल्लारी, तोरनागल्लू, होसपेटे और गिनिगेरा खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ प्रमुख स्टील और पावर प्लांट हैं, ऐसे में बेहतर माल ढुलाई और दबाव कम होने से काफी लाभ होगा।

iv. गुंटकल - वाडी स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरने वाली गुंटकल और वाडी के बीच 230 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना मौजूदा डबल-लाइन सेक्शन को चार लाइन वाला बना देगी, जिससे सबसे महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्गों में से एक इस खंड पर पर क्षमता बढ़ेगी।

यह कॉरिडोर नागपुर-बलहारशाह-कोठागुडेम बेल्ट से वाडी-गुंटकल-रेनिगुंटा एक्सिस के साथ ऊर्जा संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है और वाडी तथा तांदूर के बीच प्रमुख सीमेंट उद्योगों की सहायता करता है। इस विस्तार से रुकावटें कम होंगी, समय पर माल ढुलाई सुनिश्चित होगी, औसत गति में सुधार होगा, और यात्री और मालगाड़ियों दोनों के लिए अतिरिक्त रास्तों का विकल्प होगा।

v. सेलम-करूर-डिंडीगुल के बीच दोहरिकरण

रेल मंत्रालय ने यात्री भीड़ का दबाव कम करने, लाइन की क्षमता बढ़ाने और यात्री तथा मालगाड़ी के संचालन को आसान व तेज बनाने के लिए 159.26 किमी लंबे सेलम-करूर-डिंडीगुल रेलवे कॉरिडोर के दोहरिकरण का प्रस्ताव दिया है।

मेट्टूर थर्मल पावर प्लांट और स्टील, सीमेंट, कपड़ा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सेवा देने वाले एक प्रमुख ऊर्जा और औद्योगिक मार्ग के रूप में, अपग्रेड की गई लाइन से माल ढुलाई की लागत में काफी कमी आएगी, मालढुलाई दक्षता में सुधार होगा

सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि आयात और निर्यात की करती है निगरानी ।

(जीएनएस)।

सरकार देश के आयात और निर्यात गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है और घरेलू हितों की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार व्यापार नीतियों में संशोधन करती है। आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग सहित एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित है। यह आवश्यक कृषि उत्पादों पर कड़ी और नियमित निगरानी रखती है। उनकी उपलब्धता और बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करती है। यह समिति आयात में किसी भी वृद्धि पर भी नजर रखती है ताकि घरेलू उत्पादन, व्यापार या खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले रुझानों की तुरंत पहचान की जा सके। किसानों के हितों की रक्षा और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) कृषि उत्पादों के आयात की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्रालय/विभाग को आयात शुल्क या बंदरगाह प्रतिबंध जैसे उपायों की सिफारिश करता है। इसके अलावा सरकार कई योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। इनमें शामिल हैं:

- अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के अंतर्गत खरीद के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप;
- प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) का संचालन,
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बाजार संबंधी जानकारी और बफर स्टॉक संचालन और
- आय में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए पीएम-किसान जैसी इनपुट और आय सहायता योजनाएं।

इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य बाजार में व्यवधान के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

वाणिज्य विभाग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के अंतर्गत देश भर के अपने सदस्य निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विशेष रूप से किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के संबंध में एपीडा अपने पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से अच्छी कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से देश भर में लगभग 1080 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें निर्यातकों, किसान संगठन/परिवारिक संगठन/स्वयं सहायता समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। ताकि किसान समूहों को निर्यात आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा सके और उद्यमियों को संभावित निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अंत में एपीईडीए ने अपने सदस्य निर्यातकों एफपीओ और एफपीसी भागीदारी को विदेशों और भारत में आयोजित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड, भारत में आहार और गल्फ फूड आदि में आयोजित किया।

मुंडन संस्कार कराने जा रही महिलाओं बच्चों से भरी पिकअप बाइक सवार को बचाने में पलटी, 10 घायल चार बांदा रिफर

(जीएनएस)।

कमासिन बांदा 19 दिसंबर यमरेही नाथ धाम के ग्राम बंथरी निवासी छोटटन वर्मा अपने पुत्र का मुंडन संस्कार कराने रिश्तेदारों परिवार जनों महिलाओं छोटे बच्चों के साथ ग्राम बाकल स्थित जोगनी माता मंदिर प्रातः 9:00 बजे घर से पिकअप में सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में कमासिन राजापुर मार्ग पर भोमदत्त गुप्ता के आवास के समीप एक तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे पिकअप में सवार महिलाओं पुरुषों बच्चों में चीख पुकार मच गई घटना की सूचना तत्काल प्रत्यक्षदर्शियों ने कमासिन पुलिस को सूचना दी दुर्घटना में सभी घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस द्वारा प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में भर्ती कराया दुर्घटना में घायल महिलाओं में कल्ली उम्र 40 वर्ष पत्नी लक्ष्मण वर्मा गिरिजा देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी श्रीपाल सलोनी उम्र 11 वर्ष पुत्री नाथू प्रसाद तेजिया उम्र 50 वर्ष पत्नी राम सुमेर चुनकी उम्र 24 वर्ष पत्नी उत्तम प्रसाद

अजय कुमार 6 माह पुत्र उत्तम नथिया 30 वर्ष पत्नी नत्थू प्रसाद नीतू 15 वर्ष जय देवी 13 वर्ष पुत्री बोधी शिवऔतार उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करके गंभीर रूप से घायल नथिया उम्र 30 वर्ष जय देवी उम्र 13 वर्ष शिवऔतार उम्र 40 वर्ष नीतू उम्र 15 वर्ष को बांदा जिला अस्पताल इलाज हेतु रिफर किया गया प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश राजपूत ने बताया कि दुर्घटना में घायल सभी महिलाओं बच्चों पुरुषों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई गंभीर रूप से घायल चार मरीजों को बांदा जिला अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया थाना कमासिन पुलिस ने वाहन चालक आशीष कुमार से घटना की पूछताछ कर पिकअप को थाने में खड़ा करा लिया ।मिली जानकारी के अनुसार जोगनी माता मंदिर मुंडन संस्कार में जाने के लिए पिकअप में लगभग 30 महिलाएं बच्चे पुरूष सवार थे अचानक हुई दुर्घटना से परिवार जनों में चीख पुकार मच जाने से मुंडन संस्कार कार्यक्रम नहीं हो सका ।

योगी सरकार साइबर क्राइम के खिलाफ युद्ध में स्टूडेंट्स को बनाने जा रही साइबर योद्धा

बांदा में विशाल साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का हुआ आयोजन

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने दिया पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्थानीय लोगों व स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण

कार्यशाला में एडीजी जोन प्रयागराज हुए शामिल

रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में हुआ कार्यशाला का आयोजन

(जीएनएस)।

बांदाः 19 दिसंबर- योगी सरकार साइबर क्राइम के खिलाफ युद्ध में स्टूडेंट को अब साइबर युद्ध बनाने जा रही है। इसी के क्रम में शुक्रवार को एक विशाल साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता शामिल हुए। कार्यशाला में चित्रकूट मंडल के सभी एसपी समेत सभी पुलिसाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोग व स्कूली बच्चे भी इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए। जिन्हें मुख्यालय से आये साइबर एक्सपर्ट्स ने साइबर अपराध कैसे होता है व इसे कैसे बचा जाए इस संबंध में प्रशिक्षण दिया।

आये दिन लोग होते हैं साइबर ठगी का शिकार, जिसको लेकर सरकार अलर्ट

बता दे की आए दिन साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं और साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई पर डांका डाल रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराध से निपटने के लिए योगी सरकार अलर्ट पर है। और लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए सरकार साइबर अपराध से संबंधित कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। और स्कूली बच्चों व आम लोगों को साइबर अपराध के बारे में बताया जाए इसको लेकर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। जिसके क्रम में चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। और कार्यशाला के माध्यम से साइबर से कैसे बचा जाए इस संबंध में यहां पर आए हुए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में लोग शामिल हुए।

ऐप के जरिये भी साइबर ठग लोगों को बनाते हैं शिकार

साइबर एक्सपर्ट्स रक्षय टंडन ने बताया कि आजकल साइबर अपराध बहुत गया है और रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की बहुत जरूरत है और आजकल फ्रॉड कॉल के माध्यम से लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वहीं मौजूदा समय में एप के माध्यम से भी लोग साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि साइबर ठग आपके मोबाइल में एप भेज देते हैं। और उसको डाउनलोड करने के बाद मोबाइल का सारा डाटा साइबर ठगों के पास पहुंच जाता है। इसलिए जागरूकता ही बचाव है। और आज यहां पर आए हुए लोगों को साइबर अपराध के सम्बंध में जागरूक किया गया है।

एडीजी बोले साइबर अपराधियों से सभी को बचाना है प्राथमिकता

वही प्रयागराज जॉन के एडीजी संजीव गुप्ता ने बताया कि आज चित्रकूट मंडल के चारो जनपदों के पुलिस अधिकारियों, बांदा के आमजन, स्कूली बच्चे सभी को इस कार्यशाला में बुलाया गया था। और इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया है। और बताया गया है कि कैसे साइबर अपराध से बचा जाए। साथ ही यहां पर आए हुए सभी लोगों से यह भी अपील की गई है कि वह लोग अन्य लोगों को भी साइबर अपराध के बारे में बताएं। जिससे कि सभी लोग जागरुक हो सके और साइबर अपराधियों का शिकार न हो।

सैंड ऑफ आर्ट शॉ के माध्यम से दिखाई जाएगी वीर साहिबजादों की जीवन गौरव गाथा

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में आज होगा सैंड ऑफ आर्ट कार्यक्रम

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। वीर बाल दिवस 2025 के उपलक्ष्य एवं छोटे वीर साहिबजादों की जीवन गौरव गाथा को युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश में सैंड ऑफ आर्ट शॉ का आयोजन किया जा रहा है। रेवाड़ी में यह कार्यक्रम शनिवार, 20 दिसंबर को पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में आयोजित किया किया जाएगा। इसके अलावा साहिबजादों की वीरगाथा विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में सैंड ऑफ आर्ट शॉ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शॉ के माध्यम से श्री गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहादत, मुगलों के जुल्म और साहिबजादों की वीरगाथा को युवा पीढ़ी के समक्ष रखा जाएगा। साहिबजादों की वीरता, त्याग और बलिदान को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए साहिबजादों की वीरगाथा विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा।

रेवाड़ी की सुषमा यादव ने रचा इतिहास, इतिहास में हरियाणा का पहला पदक

60 साल की उम्र में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सोने पर लगाया निशाना

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। किसी ने सच ही कहा है कि जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। इस कथन को रेवाड़ी के सेक्टर-3 की निवासी सुषमा यादव धर्मपत्नी अनिल यादव ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से चरितार्थ कर दिखाया है।

नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 11 से 18 दिसंबर तक आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सुषमा यादव ने 10 मीटर सीनियर महिला पिस्टल (सीनियर मास्टर्स वर्ग) में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की, बल्कि इस वर्ग में हरियाणा प्रदेश को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया। उनकी इस शानदार उपलब्धि से रेवाड़ी जिला ही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। एक कुशल गृहिणी होने के साथ-साथ सुषमा यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

इससे पहले सुषमा यादव ने देहरादून में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर क्वालीफाई किया था। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी उन्होंने इसी वर्ग में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सुषमा यादव ने खेल, शिक्षा और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखते हुए प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत उदाहरण दिया है। आज जब हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं, ऐसे समय में सुषमा यादव जैसी महिलाएं यह संदेश देती हैं कि महिलाएं स्वयं आगे बढकर न केवल अपने लक्ष्य हासिल कर सकती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी विशेषकर बेटियों को भी आगे बढऩे की प्रेरणा दे सकती हैं। अपनी इस गौरवपूर्ण सफलता का श्रेय सुषमा यादव ने अपने कोच रमन तथा अपने परिजनों को दिया है।

संगठन की शक्ति से ही फलीभूत होगा 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्पः सुरेन्द्र पूनिया

रेवाड़ी के कोसली विधानसभा में उमड़ा शक्ति केंद्र प्रमुखों का सैलाब, प्रदेश महामंत्री ने फूंका कार्यकताओं में जोश

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री सुरेन्द्र पूनिया जी ने आज रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र का सघन प्रवास किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बुडोली जी के कुशल नेतृत्व में शुरू किए गए इस संगठनात्मक अभियान के तहत, सुरेन्द्र पूनिया जी के कोसली विधानसभा के प्रत्येक मंडल में शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी ने की बैठक को मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी ने संबोधित किया और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक विस्तृत और महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की जमीनी इकाइयों को मजबूत करना और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना रहा। इस प्रवास के दौरान जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना पोपली जी मुख्य रूप से उपस्थित रही। साथ ही, जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल, कुलदीप चौहान, , जिला सचिव दिनेश यादव, प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष नीतू चौधरी सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष हरीश गोपी अनूप सविता और मण्डल प्रभारी प्रेम कौशिक जितेन्द्र यादव खोल इन्द्र राव सरदार सिंह बहाला और गणमान्य पदाधिकारी पूरे समय सुरेन्द्र पूनिया जी के साथ रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री सुरेन्द्र पूनिया ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर विशेष बल दिया। उन्होंने रेवाड़ी के कार्यकताओं की ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कहा कि, "भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है। हमारी शक्ति हमारे पद नहीं, बल्कि हमारे शक्ति केंद्रों की सक्रियता है।"उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश को विश्व पटल पर अग्रणी बनाने का मार्ग है, जिसे भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं। उन्होंने मंडल स्तर पर मोर्चा और शक्ति केंद्रों को और अधिक धारदार बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी दिए।

पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करते हुए श्री पूनिया ने हाल ही में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण परिवार से आने वाला सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत और निष्ठा के दम पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह वंशवाद की राजनीति के अंत और आंतरिक लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है।

जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने अपने संबोधन में आगामी 25 दिसंबर (अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती) के कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि जिला भाजपा मुख्यालय पर सुशासन दिवस के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। 25 दिसंबर को हम न केवल उन्हें याद करेंगे, बल्कि 'सुशासन' के उनके संकल्प को हर घर तक पहुँचाएंगे। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह जनता की सेवा में तत्पर है। शक्ति केंद्रों की यह मजबूती आने वाले समय में एक नए और विकसित हरियाणा की नींव रखेगी।

उन्होंने सुरेन्द्र पूनिया जी और सभी उपस्थित कार्यकताओं का बैठक को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में कोसली विधानसभा के मंडलों से भारी संख्या में सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों और मण्डल पदाधिकारियों ने साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे संगठन की एकजुटता का परिचय मिला।

रेवाड़ी की प्यास पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की विधानसभा में दहाड़, लिसाना वाटर स्टोरेज टैंक के लिए भूमि अधिग्रहण की मांग

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर की गंभीर पेयजल समस्या को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा के विंटर सेशन में एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने गांव लिसाना में प्रस्तावित वाटर स्टोरेज टैंक के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की जोरदार मांग उठाई।

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सदन में कहा कि वर्तमान में रेवाड़ी शहर के लोगों को तीन दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लिसाना गांव में वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण की प्रक्रिया पिछले करीब दो वर्षों से लंबित है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना के लिए दो एग्रीगेटर नियुक्त किए गए थे, जिनमें से एक एग्रीगेटर द्वारा 45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि दूसरा एग्रीगेटर निष्क्रिय है। विधायक ने कहा कि उसी गांव में आवश्यक भूमि उपलब्ध है और किसान भी ई-भूमि पोर्टल पर अपने हलफनामे दे चुके हैं। ऐसे में सरकार को बिना देरी किए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीदनी चाहिए, अन्य स्थान देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधायक ने यह भी कहा कि भगवानपुर की भूमि के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जबकि लिसाना वाटर स्टोरेज टैंक रेवाड़ी शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर जल्द से जल्द भूमि खरीदकर परियोजना को पूरा कराया जाए।

लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जैसे ही यह परियोजना पूरी होगी, रेवाड़ी शहर के लोगों को पर्याप्त और नियमित पेयजल सुविधा मिल सकेगी। विधायक की इस मांग पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में आश्वासन दिया कि सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराएगी।

इसके साथ ही विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की भी खुलकर सराहना की।

बांदा में दर्दनाक सड़क हादसाः दो युवकों की मौत, एक गंभीर

(जीएनएस)।

बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में ग्राम दोहतरा के पास मेन रोड पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा 18 दिसंबर 2025 को हुआ।

मृतकों की पहचान सरवर (25 वर्ष) पुत्र इसरार अहमद और इशरत खान (30 वर्ष) पुत्र फारूक, निवासी ग्राम ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर के रूप में हुई है। घायल प्रमोद कुमार पुत्र जयकरण वर्मा, निवासी ग्राम दिघवाट थाना चिल्ला जनपद बांदा को जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इंचार्ज परिवाद शाखा निरीक्षक सुनीता के स्थानांतरण पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रेवाड़ी में विदाई समारोह आयोजित

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। इंचार्ज परिवाद शाखा निरीक्षक सुनीता के जिला रोहतक में स्थानांतरण होने पर शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह में डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ रविंद्र सिंह सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रमे में निरीक्षक सुनीता को स्मृति स्वरूप उपहार भी भेंट किए गए।

इस अवसर पर डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ रविंद्र सिंह ने कहा कि निरीक्षक सुनीता ने जिला रेवाड़ी में अपने कार्यकाल के दौरान कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया है तथा अपने उच्च अधिकारियों, समकक्ष व अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर तालमेल के साथ कार्य किया है जिसके लिए वे बधाई की पात्र है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निरीक्षक सुनीता जिला रोहतक में भी इसी तरह सराहनीय कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर मुख्य लिपिक निरीक्षके सुनीता, स्टेनो निरीक्षक अनिल कुमार, प्रवाचक पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी एएसआई तेजपाल व सुरक्षा शाखा प्रभारी एएसआई सतपाल सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने निरीक्षक सुनीता के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विकास कार्यों को लेकर जिला परिषद की हुई बैठक

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। जिला परिषद की शुक्रवार को लघु सचिवालय रेवाड़ी के सभागार में जिला परिषद के प्रधान मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सरकार की विभिन्न स्कीमों 15वें केन्द्र वित्त आयोग से वर्ष 2025-26 मे टाइड, अनटाइड व एस.एफ.सी. में लगभग 4 करोड़ की राशि के 69 विकास कार्यों को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैठक में पी.डब्ल्यू.डी व एच.एस.एम.बी. विभाग को सडकों पर तुरंत प्रभाव से सफेद पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए । वहीं अन्य विभाग के अधिकारियों को भी जिला पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की हिदायतों अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप प्रधान जिला परिषद नीलम, एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राहुल मोदी, जिला पार्षद, डीडीपीओ एचपी बंसल, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज नरेंद्र गुलिया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।